वर्ष-8 अंक 46 08 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक पृष्ठ-12 MPHIN/2015/63623

न्यूज क्राइम फाइल

आमंत्रण मुल्य 15/-

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, हरदा एवं इंदौर में प्रसारित।

चेक पोस्ट चौकियां बंद, कई कर्मचारी बेरोजगार...

चेक पोस्ट पर काम करने वाले प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को अब आर्थिक भार से जूझना पड़ रहा

उदय प्रताप सिंह चौहान

सूबे की मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की चेक पोस्टों को खत्म कर दिया है। जिसके बाद चेक पोस्ट पर काम करने वाले प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को अब आर्थिक भार से जूझना पड़ रहा है। सरकार के इस तानाशाही फैसले से चेक पोस्ट चौकियों पर काम करने वाले प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों में जमकर आक्रोश उबर पड़ा है। उनका कहना है कि आरटीओ और परिवहन विभाग को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं हुआ। यह नुकसान प्राइवेट कंपनी में चेक पोस्ट पर दिन रात मेहनत करने वाले ऑपरेटर सुपरवाइजर क्लीनर जैसे आदि कर्मचारियों का हुआ है। कर्मचारियों को कहना है सरकार को पूर्ण विचार करके यह फैसला लेना चाहिए था। सरकार के इस फैसले से हम हमारे परिवार का भरण पोषण अब कैसे करेंगे।

चेक पोस्ट कर्मचारियों की मांग सरकार हमारी नौकरी की व्यवस्था करें

चेक पोस्ट बंद होने के बाद कई सालों से नौकरी करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर अब बेरोजगार हो चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे क्योंकि इस उम्र में हम अब कहां नौकरी तलाश करने जाएंगे। यदि सरकार अपने फैसले पर विचार विमर्श नहीं करती है तो पूरे प्रदेश के चेक पोस्ट कर्मचारी उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे।

211 होमगार्ड्स के जवानों नियुक्ति, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को कुछ नहीं

मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में संचालित परिवहन चेक पोस्ट की जगह 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट और 94 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट के लिए 211 होमगार्ड्स के जवानों की जिले वार प्रतिनियुक्ति की गई है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी डयूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा। परंतु चेक पोस्ट चौकियों पर काम करने वाले प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का ख्याल शायद सरकार को नहीं है। 10 सालों से अधिक समय से नौकरी करने वाले कर्मचारी आज बेरोजगार घूम रहें है और मोटी सैलरी लेकर मलाई खाने वाले सरकारी कर्मचारी मौज की जिंदगी जी रहें है।

चेक पोस्ट के कर्मचारियों को छोड़ परिवहन मंत्री को बाकी सबका ख्याल

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने को चेक पोस्ट के कर्मचारियों को छोड़ बाकी सबका ख्याल है। क्योंकि परिवहन मंत्री ने प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों को छोड़कर बाकी अमले की भर्ती जल्दी होगी। यह बात कहीं थी लेकिन परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को चेक पोस्ट पर काम करने वाले गरीब कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। सत्ता के अहंकार में रहने वाले परिवहन मंत्री शायद यह भुल गये है कि अहंकार रावान का भी नहीं रहा है।

यह पूरा मामला

सीएम डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि सुशासन के अंतर्गत कई काम किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। सीएम ने कहा- परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें मिलने पर राज्य शासन सख्त कार्रवाई करेगा। नई व्यवस्था से ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के इंतजाम किए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़न दस्ते कार्य करेंगे।

मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलना था...

विधानसभा मानसून सत्र 5 दिन में ही खत्म...

संजीव कुमार

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन में ही खत्म हो गया। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी। 1 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलना था। इससे पहले 3 जुलाई मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी बहस हुई। शुक्रवार को 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट बहुमत से पारित किया गया। वहीं सरकार ने 6 विधेयक भी पारित करा लिए। शुक्रवार को दिनभर चली सदन की कार्यवाही में कई बार हंगामे की स्थिति बनी और एक बार सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। प्रशनकाल के दौरान कांग्रेस के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जल जीवन मिशन में किए गए भ्रष्टाचार के मामले उठाए।

नेता प्रतिपक्ष बोले- विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिला

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विपक्ष पर हंगामा कर सदन नहीं चलने देने के आरोप लगाए जाते हैं। विपक्ष ने इस बार सदन में हंगामा किया, लेकिन सदन चलने में असहयोग नहीं किया। इसके बाद भी विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिला।

बीजेपी विधायक बोले- नई तालीम से नया तालिबान खड़ा मत करो

सदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा समेत कई मुद्दे उठाए गए।

बीजेपी विधायक अभिलाष पांडेय ने संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। यह मदरसों जैसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने से जुड़ा है। सरकार से इस पर रिव्यू की मांग की गई। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, नई तालीम से नया तालिबान खड़ा मत करो। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सबको शिक्षा और रोजगार मिले। मदरसा यदि मजहब की बात करता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है तो यह दुर्भाग्य है। मदरसा यदि डॉक्टर-इंजीनियर देता है तो समझ में आता है। एक अकेले उर्दू के बलबूते पर सभी शिक्षाएं नहीं

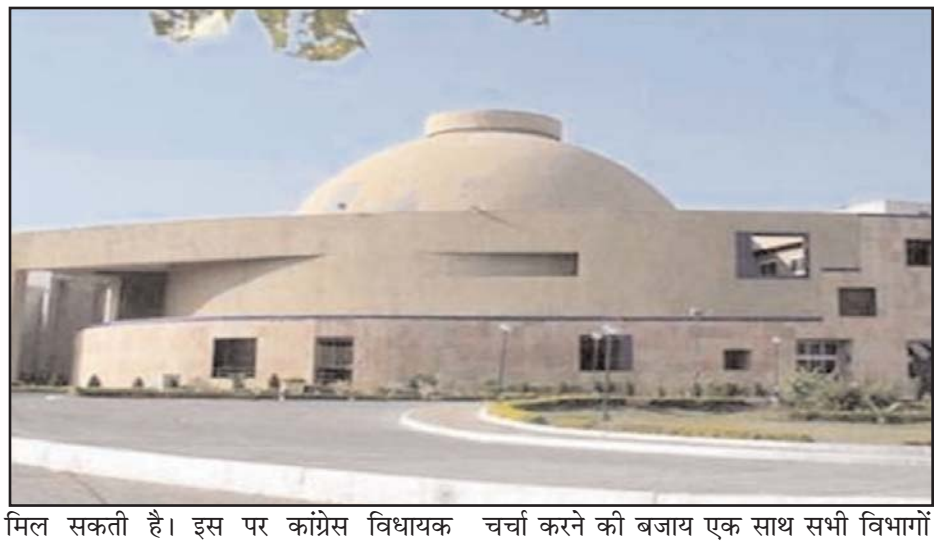

मिल सकती है। इस पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा- नर्सिंग घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक मदरसों का मुद्दा उठा रहे हैं।

गोवंश वध विधेयक पर मरकाम के बयान पर हंगामा

गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम पर चर्चा करते हुए विधायक ओंकार सिंह मरकाम

ने कहा कि सदन के बाहर सभी धर्मों की एक बैठक बुलाई जाए और गो वंश के महत्व को समझाया जाए। गो वंश की जीवन की रक्षा जरूरी है। इसके लिए सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। सड़क पर गो माता की जो मौतें होती हैं उससे बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के किनारे शेड बनाए जाने चाहिए। गो माता पर राजनीति करने के बजाय वास्तविक रूप से गो माता के संरक्षण को समझना और सोचना पड़ेगा। मरकाम ने कहा कि गो माता की मृत्यु पर खुले में छोड़ दिया जाता है और जो व्यक्ति गाय के चमड़े को निकाल कर उसे ढोलक तैयार करता है वही ढोलक मंदिर में बजती है। लेकिन जो व्यक्ति :ये काम करता है उसे अछूत कहा जाता है। मरकाम के इतना कहने के बाद भाजपा विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया और सदन में बहस की स्थिति बन गई। मरकाम ने पहले तो इस मामले में क्षमा मांगी लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह चार बार के विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं लेकिन आज भी अगर वह किसी के घर जाते हैं और भोजन करते हैं तो उन्हें थाली धोने पड़ती है उसके बाद हंगामा होने लगा। विधानसभा में सभी विधेयक पारित होने के बाद जब अनुदान मांगों पर चर्चा का मामला आया तो संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव रखा कि विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा करने की बजाय एक साथ सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाए। इस पर उन्होंने विपक्ष की सहमति चाही, जिसका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विरोध किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा तो अध्यक्ष ने बहुमत के आधार पर एक साथ चर्चा करने का फैसला लिया। इस पर कांग्रेस ने विरोध किया और शोर शराबे की स्थिति बन गई। एक ओर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शोर शराबे के बीच विभागीय अनुदान मांगों को पारित करने जाने का प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो दूसरी ओर सदन में कांग्रेस सदस्य हंगामा करते रहे और विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की मांग करते रहे। कांग्रेसी सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे।

जल जीवन मिशन में करप्शन का आरोप, विपक्ष का वॉकआउट

विधानसभा में प्रशनकाल के दौरान जल जीवन मिशन के कामों में करप्शन का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर लें तो मिशन की सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी बोले कि कई जगह ऐसी भी हैं, जहां नल लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं आता है। उनकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सदन में शोर-शराबे की स्थिति बनी तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रश्नकाल के दौरान इस तरह की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए। अनुमति लेकर अपनी बात कहनी चाहिए। इससे असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्य बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- जल जीवन मिशन में शिवराज सरकार के समय से घोटाला किया जा रहा है। अब डॉ. मोहन यादव की सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। जो जनता को पानी मुहैया नहीं करा पा रही है, वह सरकार फेल है।

ये 6 विधेयक पारित

मप्र माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 : इसमें यह प्रावधान है कि पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी की व्यवस्था तय की गई है।

मप्र गोवंश वध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 : इसमें गोवंश का परिवहन करने वाले वाहनों को प्रशासन राजसात कर सकेगा। कलेक्टर के आदेश के बाद कोई न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। अब तक सिर्फ वाहन जब्त करने का अधिकार प्रशासन के पास था।

मप्र मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक 2024 : इसमें यह प्रावधान है कि अब कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव को मिलने वाले भत्ते और किराए पर लगने वाले इनकम टैक्स की राशि का भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी बल्कि यह टैक्स संबंधित व्यक्ति खुद भरेगा।

मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक 2024 : इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद कुलगुरु के नाम से पुकारा जाएगा।

मप्र खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024 : इसमें नलकूप की ड्रिलिंग की जिम्मेदारी तय करने के साथ भूमि स्वामी और ड्रिलिंग एजेंसी पर कार्रवाई तय करने का प्रावधान है। साथ ही खुले बोरवेल या नलकूप के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए किसी सरकारी अधिकारी को कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं।

मप्र सुधारात्मक सेवाएं और बंदीगृह विधेयक 2024 : इस विधेयक के माध्यम से जेलों की सेवा में वृद्धि किए जाने और बंदियों के लिए सुरक्षा देने का काम किया जा सकेगा। बंदियों द्वारा जेल में अवैध रूप से ली जाने वाली सेवाओं पर भी इस विधेयक के माध्यम से कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं।

साथी ने बनाया वीडियो, रेल एप मदद पर किया अपलोड; डीआरएम ने किया सस्पेंड

यात्री से रिश्वत ले रहे थे टीटीई

न्यूज क्राइम फाइल

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में पदस्थ एक टीटीई का यात्री से रुपए लेते हुए का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जब रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचा तो टीटीई पर कार्रवाई करते हुए डीआरएम ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। टीटीई का नाम नागेन्द्र कुमार है, जो कि स्लीपर में यात्री को सीट देने के लिए 200 रुपए ले रहा था। यात्री से रुपए लेने का वीडियो पास ही बैठे एक यात्री ने बनाया और फिर उसे रेल मदद एप पर अपलोड कर दिया। वीडियो जब रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचा तो इस गंभीर लापरवाही मानते हुए टीटीई नागेन्द्र कुमार को निलंबित करते हुए जबलपुर डीआरएम ऑफिस में अटैच किया गया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रेल मदद एप बनाया है, जिसमें आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल गुरुवार को प्रयागराज से मुंबई जा रही ट्रेन में टीटीई नागेन्द्र कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी। ट्रेन में जब नागेन्द्र यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे, उस दौरान एक यात्री जिसके पास जनरल डिब्बे की टिकट थी, वह स्लीपर कोच में आकर बैठ गया था। ट्रेन प्रयागराज से मुंबई के लिए चली तो टीटीई पहुंचे और एक यात्री

की टिकट चेक करते हुए उस पर कार्रवाई करने की बात कहने लगे। यात्री ने कहा कि उसे सतना तक जाना है। टीटीई ने पहले पांच सौ रुपए देने को कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि आप 200 रुपए दे दीजिए, सतना तक ही इंतजार करूंगा, उसके आगे गए तो फिर तुम्हारी टिकट बना दी जाएगी। टीटीई और यात्री के बीच करीब दो मिनट तक बात चली, जिसका कि एक यात्री ने वीडियो भी बना लिया था। रेल एप के माध्यम से शिकायत सामने आते ही डीआरएम ने टीटीई नागेन्द्र को निलंबित कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल मदद एप को इजात किया है, इस एप के माध्यम से यात्री सफर के दौरान किसी भी समस्या को लेकर शिकायत कर सकते है। टीटीई नागेन्द्र कुमार के खिलाफ इसी एप के माध्यम से शिकायत मिली थी। रेल मंत्रालय के निर्देश पर हर मंडल में शिकायत का निराकरण के लिए वार रूम बनाया गया है। जहां पर आने वाले यात्रियों की शिकायत को दर्ज किया जाता है। लगातार यात्रियों के द्वारा अतिरिक्त पैसा लेने और सीट देने की भी शिकायत आ रही है।

ऐसे किया जा सकता है इसका उपयोग

रेल में सफर के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, या फिर शिकायत है तो उसके लिए आप अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही रेल मदद (रेल मदद) एप के जरिए रेल अधिकारियों तक बात पहुंचा सकते है। जिसके बाद तुरंत ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर रेल मदद एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके बाद आपके पास शिकायत को लेकर कई आप्सन खुल जाएगे, जिसमे कि ट्रेन कम्प्लेन से लेकर स्टेशन,पार्सल जानकारी, ट्रेक शिकायत और सुझाव के ऑप्शन आ जाएंगे। एप पर अपनी शिकायत, जिसकी शिकायत करना है उसकी डिटेल के साथ तारीख और यात्रा की जानकारी देकर उस सबमिट कर सकते है। रेल मदद एप पर फोटो-वीडियो को अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है।

भोपाल में बाल आयोग ने की मदरसों की जांच

न्यूज क्राइम फाइल

मध्य प्रदेश बाल आयोग की टीम ने भोपाल के मदरसों का निरीक्षण किया। टीम सबसे पहले पांच नंबर स्थित माचना कॉलोनी में सिद्दीकिया दारुल उलूम मदरसा पहुंची। मदरसा रविवार की जगह आज शुक्रवार को बंद मिला। आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने बताया कि यहां सरकारी नियम के अनुसार रविवार को छुट्टी रहना चाहिए। लेकिन, यहां आज शुक्रवार को छुट्टी रहती है। इसकी जांच करेंगे। बाकी यहां सब ठीक है। डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि ये मदरसा रजिस्टर्ड है। मदरसों का रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है। एक तरह के मदरसे वे होते हैं। जो शासकीय सहायता लेते हैं। इनमें मिड डे मील के अलावा अन्य चीजों में सरकार सहायता करती है। जबकि ये मदरसा सिर्फ रजिस्टर्ड है। मदरसे के सदस्य मो.

रविवार की जगह होती है जुम्मे की छुट्टी

फैजान ने बताया कि आज जुम्मा(शुक्रवार) होने के कारण यहां छुट्टी है। मदरसे में रविवार को भी पढ़ाई होती है। यहां हिंदी, इंग्लिश, अरबी के साथ सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। रविवार की की जगह शुक्रवार को छुट्टी होने पर उन्होंने पर उन्होंने कहा कि शरीयत में जुमा एक बहुत बड़ा दिन होता है। बच्चे नमाज के साथ बाकी काम भी शुक्रवार को ही करते हैं। इसलिए यहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहती है।

विधायक आतिफ अकील ने जताई नाराजगी

मॉचना कॉलोनी स्थित मदरसे की जांच पर भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार जब-जब भ्रष्टाचार में फंसती है उससे बचने के लिए ऐसे काम करने लगती है। हमारे यहां जैन संतों पर अत्याचार हुए। सरकार ने इस मामले में आज तक कुछ नहीं किया। जिस स्थान पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वहां के प्रिंसिपल चंदा करके उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्था करते हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों के दिमाग में जो वायरस घुसा है उसे निकालना चाहिए।

आंगनवाड़ी केंद्र का भी किया निरीक्षण

माचना कॉलोनी के मदरसे की जांच करने के बाद बाल आयोग की टीम 6 नंबर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र 1011 पर पहुंची। यहां मध्याह्न भोजन की जांच की। बाल आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता ने कहा कि आंगनवाड़ी अच्छी है। ठीक ढंग से भोजन दिया जा रहा है। बच्चों की देखभाल भी सही तरीके से हो रही है। इस केंद्र में 3 से 6 उम्र के 29 और 0 से 3 साल के 49 वर्ष के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बताया कि यहां एक कमी मिली है। वॉशरूम में पानी की दिक्कत थी। इसे सही कराने कहा गया है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों का खर्च बढ़ा

केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकाल के मुकाबले तीसरी बार के कार्यकाल के लिए उनकी पार्टी भाजपा को जनादेश कम मिलने का रहस्य उनकी आर्थिक नीतियों में भी छिपा है, जो यह चुगली कर रहा है कि इनके पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भारत के लोगों की शुद्ध बचत में गिरावट आई है, जबकि खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनकी सरकार के मातहत काम करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-2024 बोल रही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक यानी मोदी युग में न केवल लोगों की शुद्ध बचत घटी है, बल्कि इसी बीच आई वैश्विक कोरोना महामारी के चलते भी लोगों के बचत करने के व्यवहार में आमूल चूल बदलाव आया है। यदि मोदी सरकार इसे समय रहते ही समझ गई होती तो उसे गठबंधन की बैशाखी पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और न ही 400 पार का सपना टूटता। अब बात करते हैं आरबीआई की इस रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक, देशवासियों के बीच बचत कम होने के दो मुख्य कारण हैं- पहला यह कि अब लोग सोना-चांदी, जमीन-घर और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। और दूसरा यह कि, लोगों का घरेलू खर्च यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आम उपभोग आदि बढ़ा है, जिसकी वजह से शुद्ध वित्तीय बचत में भारी कमी दिखाई पड़ी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल बचत दर में सकल शुद्ध प्रयोज्य आय 29.7 प्रतिशत थी। जिसमें परिवार के प्राथमिक बचतकर्ता की हिस्सेदारी 60.9 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2013-22 के बीच का औसत 63.9 प्रतिशत रहा। इसी तरह से लोगों के पास शुद्ध वित्तीय बचत में भी 11.3 प्रतिशत की गिरावट आई है जो 2022-23 में गिरकर 28.9 प्रतिशत रह गई है, जबकि 10 वर्षों का औसत 39.8 प्रतिशत रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भले ही घरेलू बचत में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन वह ज्यादा स्थाई नहीं रह पाई। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान कुल घरेलू बचत 51.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, परंतु उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों ने अपनी बचत को सम्पत्तियों के खरीदने पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ लोगों की देनदारियों में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे नगदी के रूप में बचत गिरती चली गई। वहीं, कोरोना के बाद से लोग बचत को बैंक खातों में एफडी व अन्य रूप में रखने से बच रहे हैं। जबकि सम्पत्तियों को खरीदने के लिए कर्ज लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कृषि और व्यवसायिक लोन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जीडीपी का 40 प्रतिशत घरेलू उधार हो गया है, जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में इंडोनेशिया, मैक्सिको, पौलेंड और ब्राजील से अधिक है। वहीं, आमलोगों के खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते शुद्ध रूप से वित्तीय बचत में गिरावट आई है। यदि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के औसत के हिसाब से भी देखा जाए तो जीडीपी में शुद्ध बचत की हिस्सेदारी 2.7 फीसदी कम हो गई है। कहने का मतलब यह कि एक दशक पहले के आठ प्रतिशत से घटकर यह 2022-23 में 5.3 फीसदी पर आ गई है,जो चिंता की बात है। रिपोर्ट बताती है कि अब लोगों को शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो किसी भी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा है। सामान्य तौर पर बैंकों में सात से आठ प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिल रहा है, लेकिन शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को मोटा रिटर्न मिला है। खासकर निफ्टी में पैसा लगाने वालों को ठीक-ठाक

रिटर्न मिला है। आंकड़े बता रहे हैं कि जहां निफ्टी 50 में पहले वर्ष 29 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 13 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 15 प्रतिशत का रिटर्न मिला है, वहीं निफ्टी मिडकैप 150 में पहले वर्ष 56 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 26 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 250 में पहले वर्ष 63 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 23 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 28 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। जबकि निफ्टी माइक्रोकैप 250 में पहले वर्ष 85 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 37 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 42 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार के बीते एक दशक में जहां एक ओर लोगों का खर्च बेतहाशा बढ़ा है, वहीं आमदनी लुढ़की है और बचत घटी है। वहीं, सिर्फ शेयर धारक ही मालामाल हुए हैं। इस स्थिति से परेशान आमलोगों ने सरकार की इंजन पार्टी रही भाजपा का संख्या बल घटा दिया, ताकि वह अपने मित्र दलों की सलाह भी सुने और पूंजीवादी ताकतों के हाथों खेलने के बजाय आम लोगों के लिए भी सही नहीं बनाए। यदि अब भी वह जनभावनाओं को दरकिनार करके चलेगी तो संभव है कि जनता उसके नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को ही सत्ता से बाहर कर दे। इसलिए समय रहते सम्भलना जरूरी है, रिपोर्ट यही चुगली कर रही है।

संपादकीय

कठिन आर्थिक दौर से ब्रिटेन को बाहर निकालने का श्रेय सुनक को ही जायेगा

ब्रिटेन की जनता ने इस बार के आम चुनाव में सत्ता पलट दी है। महंगाई की सर्वाधिक मार झेलने वाली ब्रिटेन की जनता ने कंजरवेटिव पार्टी को चुनावों में कड़ा सबक सिखाया है जिसके चलते प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को माफी मांगते हुए यह कहना पड़ा है कि मैंने आपके गुस्से और निराशा को महसूस किया है और मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। वैसे चुनाव के नतीजे जो भी रहे हों लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऋषि सुनक ने अपने देश को कठिन आर्थिक परिस्थितियों के दौर से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद जब लिज ट्रस ने ब्रिटेन की कमान संभाली थी तो तुरंत ही उन्हें अर्थव्यवस्था की बिगड़ी सेहत का अंदाजा हो गया था और उन्होंने महज 45 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। उस समय ऋषि सुनक ही अंतिम तारणहार दिखाई पड़ रहे थे। देखा जाये तो ऋषि सुनक ने उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कांटों का ताज पहना था क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद हिचकोले खा रही थी। महंगाई और ब्याज दरें बढ़ रही थीं। यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा पर होने वाले खर्च को बढ़ा दिया था। मुद्रा बाजार में स्टर्लिंग (ब्रिटेन में प्रचलित मुद्रा) कमजोर दिख रही थी। एक सफल बैंकर और वित्त मंत्री रहे सुनक ने प्रधानमंत्री बनते ही बजट घाटे को काबू में किया, सरकार के खर्चों में कटौती की और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आये लेकिन वैश्विक संघर्षों के चलते बाधित हुई सप्लाई चेन की वजह से बढ़ती महंगाई को वह नहीं रोक पाये। इसके अलावा चूंकि उनकी पार्टी पिछले लगभग डेढ़ दशक से सत्ता में थी इसलिए ब्रिटेन में इस बार बदलाव की जोरदार लहर चल रही थी जोकि परिणामों में स्पष्ट नजर आ रही है। वैसे ब्रिटेन के आम चुनावों में बदलाव होने वाला है इसके संकेत पिछले साल हुए उपचुनावों में ही मिल गये थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऋषि सुनक की वैश्विक लोकप्रियता में तो इजाफा हुआ था लेकिन ब्रिटेन में पिछले साल तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में उनकी कंजरवेटिव पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। अब आम चुनावों में कंजरवेटिव पार्टी को अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सुनक की नीतियां जनता को पसंद नहीं आ रही थीं? सवाल यह भी उठा है कि कंजरवेटिव पार्टी को गलत नीतियों की सजा चुनावों में मिली या पार्टी को एकजुट नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? सवाल यह भी है कि क्यों कंजरवेटिव पार्टी के नेता और सांसद ही अक्सर विवादों में रह कर सुनक की मुश्किलें बढ़ा रहे थे।

एम्स में पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर का उद्घाटन

सांसद आलोक शर्मा पहुंचे, कहा- डॉक्टर्स का बढ़ेगा कौशल

न्यूज क्राइम फाइल

सांसद आलोक शर्मा ने एम्स भोपाल में अत्याधुनिक पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर का उद्घाटन किया। यह 3डी प्रिंटिंग तकनीक का लेटेस्ट मॉडल है जो मल्टी डेंसिटी और और मल्टी-कलर प्रिंटिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। इस अवसर र पर बोलते हुए आलोक शर्मा ने स्वास्थ्य सेवा में इस तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा की। उन्होंने कहा पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर डाक्टरी के क्षेत्र में एक गेम चेंजर है। जो डाक्टरों को उनके कौशल को बढ़ाने और रोगी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सहायक होगा । यह सुविधा न केवल एम्स भोपाल को लाभान्वित करेगी बल्कि अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित करेगी। इस दौरान उन्होंने एम्स भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा उन्होंने कहा कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल आगे भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। इस नई सुविधा से चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और रोगी देखभाल को आगे बढ़ाने में विशेष सहायता मिलेगी। एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह ने भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे संस्थान में पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर का एकीकरण नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम इस तकनीक से मिलने वाली संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं, और हमें विश्वास है कि यह चिकित्सा प्रशिक्षण और रोगी देखभाल में हमारी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

भोपाल में 15 साल के नाबालिग ने किया सुसाइड, कारण अंजान

न्यूज क्राइम फाइल

गांधी नगर इलाके में रहने वाले 15 साल के नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शुक्रवार की रात 9 बजे की है। नाबालिग की पांच साल की भांजी ने मामा को फंदा लगाते देखा। इसी जानकारी बच्ची ने अपनी मां को दी। मां ने कमरे में पहुंचकर देखा तो उसका नाबालिग भाई फांसी के फंदे पर लटका था। चीख पुकार की तो पड़ोसी मदद के लिए आए। उन्होंने शव को फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सोनू कुमार (15) पुत्र विश्वानाथ कुमार मूल रूप से मुरैना का रहने वाला था। बीते दो सालों से बहन और जीजा के साथ राधा कृष्ण मंदिर के पीछे गांधी नगर में रहता था। गांधी नगर इलाके में ही वह फुल्की का ठेला लगाता था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुसाइड से पहले उसने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। उसका व्यौहार सामान्य ही रहता था। उसने खुदकुशी क्यों की इसकी जानकारी नहीं है।

भांजी ने पूछा था मामा क्या कर रहे हो

मृतक के पड़ोसी सोनू जाटव ने बताया कि सोनू शुक्रवार की रात को घर में अकेला था। उसके जीजा काम पर गए थे। बहन सब्जी खरीदने पास ही स्थित मंडी गई थी। घर में उसकी मासूम पांच साल की भांजी भी। उसी के सामने सोनू ने फांसी का फंदा बनाया और गले में लगा लिया। भांजी ने पूछा मामा क्या कर रहे हो, तब सोनू ने उसे कमरे से जाने के लिए कहा। भांजी तत्काल मां को बुलाने गई। उन्हें बुलाकर घर लौटी, तब तक सोनू फांसी लगाकर चुका था। फंदे पर लटके उसके शव में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने शव को उतारा और पुलिस को सूचना दी।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में ब्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बॉयोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441

संजीव कुमार (ब्यूरो प्रभारी भोपाल) 08224965455

email: newscrimefile@yahoo.com

1 पेड़ 10 बेटों के बराबर; मंत्री और सांसद-विधायकों ने भी रोपे पौधे

सीएम ने मां के नाम से लगाया पौधा

न्यूज क्राइम फाइल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में मां के नाम से आंवले का पौधा रोपा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। सीएम ने कहा, प्रदेशभर में साढ़े पांच करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। भोपाल-जबलपुर में 12-12 लाख, इंदौर में 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा, वृक्ष की वेदों में महत्ता बताई गई है। 10 कुंओं के बराबर एक बावड़ी, 10 पौधे बराबर एक बावड़ी, 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की मान्यता है। देश का 35 प्रतिशत वन हमारे मध्यप्रदेश में है। हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाए। जंबूरी मैदान में हुए कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, रायमंत्री राधा सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे।

ईओडब्लू ने पीडब्लूडी के 5 अधिकारियों पर दर्ज की एफआईआर

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में ईओडब्लू ने पीडब्लूडी के पांच अधिकारियों पर जालसाज़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों ने भोपाल के चर्चित बिल्डर और कंसलटेंट एलएन मालवीय साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सरकार को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। दरअसल, जबलपुर में पुल और सड़कों के निर्माण के लिए एल एन इंफ्रा कंपनी को कंसलटेंट बनाया गया था। विभाग ने कंसलटेंट कंपनियों के लिए 12 करोड़ का फंड रखा था। अधिकारियों ने मिली भगत कर नियम विरुद्ध 26 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी के तौर पर दिए गए। इससे सरकार को 13.86 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान पहुंचा है। कई महीनों की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है।

इन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ

तत्कालीन एई सजल उपाध्याय, एमपी सिंह एस ई, नरेंद्र कुमार डायरेक्टर एनबीडी और आर एन मिश्रा तत्कालीन फाइनेंशियल एडवाइजर पीडब्ल्यू को मामले है। इन सभी पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और साजिश के तहत भ्रष्टाचार के नियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा

मेसर्स एल एन. मालवीय इंफ्रा प्रा. लि. द्वारा फर्जी तरीके से जिन सीवी लगाकर निविदा प्राप्त की है। उनका नाम सुभाष कुमार चौधरी, उदय शंकर मलिक, मनीष कुल्हारे चन्द्रकान्तबी मुदरना, साहब सिंह हरीचरण पिता गया प्रसाद मुदगल, लोकनाटी महेश पुलोरिया अरविन्द कुमार गुप्ता है। इन सभी लोगों का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर उन्हें बीमार बताकर निविदा प्राप्त होने के पश्चात बदल दिया गया है।

फोटो कैप्शन

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने नगरीय विकास व आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के भोपाल स्थित आवास पर आयोजित सहभोज व भुट्टा पार्टी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनसे व सभी उपस्थितजन से सौजन्य भेंट की।

पंजाब पहुंचने पर अर्शदीप का जोरदार स्वागत

बोले- प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अच्छा लगा, घर जाकर मां के हाथ की रोटी खानी है

न्यूज क्राइम फाइल

भारतीय टी 20 क्रिकेट टीम के बॉलर अर्शदीप आज देर शाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। जहां से वह मोहाली के कस्बा खरड़ स्थित अपने घर पर जा रहे हैं। इसके लिए उनके घर पर स्वागत की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान की तरफ से एयरपोर्ट पर अर्शदीप सिंह का स्वागत किया गया है। यहां से उनके घर खरड़ तक विजयी मार्च निकला गया है। घर को भी फूल मालाओं के साथ सजाया गया है। घर पर सोसायटी के लोग ढोल नगाडों के साथ उनके स्वागत कर रहे है।

पीएम से मिलकर अच्छा लगा : अर्शदीप

अर्शदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहां मेरे स्वागत में आए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मैंने अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना है। और घर पर अपने मां के हाथ की रोटी खानी है।

मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकले - अर्शदीप की मां

अर्शदीप सिंह की मां बलजीत कौर ने कहा कि जब इंडियन टीम ने विश्व कप जीता था, तो मैं वहां मौके पर बैठी हुई थी और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े थे। क्योंकि मेरा बेटा अर्शदीप भी उस टीम में खेल रहा था। वहीं उनके पिता दर्शन सिंह ने कहा की मुझे भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर दुगनी खुशी हो रही है। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर, एक पिता और एक भारतीय हूं। इसका मुझे गर्व है।

पुष्प वर्षा कर किया स्वागत

अर्शदीप का मकान खरड़ की एक निजी सोसाइटी में है। सोसाइटी में पहुंचने पर लोगों ने अपने घरों की छतों से फूल बरसा कर उनका स्वागत किया।

माता-पिता ने देखे सभी मैच

अर्शदीप सिंह के पिता दर्शन सिंह और मां बलजीत कौर दोनों ञ्20 वर्ल्ड कप के सभी मैच देखने के लिए विदेश में ही थे। फाइनल जीतने के बाद पूरे परिवार में बेटे के साथ ट्रॉफी के साथ मैदान पर तस्वीर भी खिंचवाई थी। इसके बाद वह अपने बेटे अर्शदीप के साथ विशेष विमान के जरिए ही भारत लौटे थे। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अर्शदीप के साथ मुलाकात भी की। इसके बाद माता-पिता घर आ गए और अर्शदीप मुंबई के लिए रवाना हो गया था। अब आज अर्शदीप भी अपने घर पहुंच रहे हैं।

बुमराह की वजह से मिले विकेट

अर्शदीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि विदेशी खिलाड़ियों पर बुमराह दबाव बनाते थे। उनके बाद जब मुझे गेंदबाजी करने का मौका मिलता था, तो वह आउट हो जाते थे। उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में 17 विकेट लिए हैं। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन विकेट, बांग्लादेश के खिलाफ दो विकेट, अफगानिस्तान के खिलाफ तीन विकेट, अमेरिका के खिलाफ चार विकेट, आयरलैंड के खिलाफ दो विकेट और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक विकेट लिया।

जून-24 में देशभर में 18.95 लाख गाड़ियां बिकीं

न्यूज क्राइम फाइल

जून 2024 में देशभर में टोटल 18 लाख 95 हजार 552 गाड़ियों की सेल हुई है। सालाना आधार पर इसमें 0.73 का इजाफा है। पिछले साल जून में 18 लाख 81 हजार 883 गाड़ियां बिकीं थीं। हालांकि, मंथली बेसिस पर सेल में 9.29की गिरावट रही है। एक महीने पहले मई 2024 में टोटल 20 लाख 89 हजार 603 गाड़ियां बिकीं थीं। यह जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जून में मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1 लाख 13 हजार 575 गाड़ियां बेचीं हैं। पिछले साल जून महीने में कंपनी ने 1 लाख 22 हजार 801 गाड़ियां बेची थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई मोटर है। कंपनी ने जून में 38 हजार 46 गाड़ियां बेची हैं। जून 2023 में हुंडई ने 44 हजार 104 गाड़ियां बेची थी।

हीरो ने सबसे ज्यादा 3.97 लाख दोपहिया गाड़ियां बेचीं

जून में टू-व्हीलर कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प ने सबसे ज्यादा 3.97 लाख गाड़ियां बेची हैं। जून में टोटल सेल में इस कंपनी का शेयर 28.86रहा है। एक साल पहले जून 2023 में कंपनी ने 32.50मार्केट शेयर के साथ 4.27 लाख गाड़ियां बेचीं थी। वहीं दूसरे नंबर पर होंडा ने 3.51 लाख टू-व्हीलर्स बेची हैं। टोटल सेल में इसका मार्केट शेयर 25.54रहा है। एक साल पहले जून में कंपनी ने 2.83 लाख गाड़ियां बेचीं थी।

मारुति ने सबसे ज्यादा 1.13 लाख कारें बेचीं

जून 2024 में मारुति सुजुकी इंडिया ने सबसे ज्यादा 1.13 लाख कारें बेची हैं। इस दौरान पैसेंजर व्हीकल्स कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर 40.34रहा है। एक साल पहले जून 2023 में कंपनी ने 1.23 लाख कारें बेची थीं, तब उसका मार्केट शेयर 40.66रहा था। इस लिस्ट में हुंडई मोटर 38,046 सेल के साथ दूसरे नंबर और 37,242 सेल के साथ टाटा मोटर्स तीसरे नंबर पर है।

भोपाल रेल मंडल में शुरू हुई सुविधा

शिकायतें सुनने के लिए रेलवे ने बनाया कंट्रोल रूम

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल मंडल में यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक मॉडर्न %वार रूम% की स्थापना की गई है। रेलवे ने कहा कि इस वार रूम का उद्देश्य यात्रियों की समस्याओं का फौरन समाधान करना है। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता नवल अग्रवाल ने कहा कि इस कंट्रोल रूम में कम्प्यूटर, इंटरकॉम, टेलीफोन, मोबाइल और बड़े स्क्रीन के साथ 24×7 की शिफ्टों में पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जब भी रेल मदद पोर्टल पर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बंधित कर्मचारी द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करते हुए यात्री से संपर्क कर उसकी समस्या को समझ कर सम्बन्धित स्टेशन को सूचित कर उसका त्वरित समाधान करवाया जाता है। मंडल द्वारा वार रूम के संचालन से मेडिकल सहायता, कोच में पानी, सफाई, बिजली आदि से संबंधित शिकायतों और सुरक्षा-संरक्षा आदि की समस्याओं का अति शीघ्र निवारण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक यह शिकायतें पहले रेलवे के अलग अलग विभागों में आती थीं। अब यह सीधे इस स्पेशल रूम में आएंगी।

यह है ख़ासियत

■शिकायतों का त्वरित समाधान- शिकायत दर्ज होने पर त्वरित निवारण किया जाता है।

■यात्री फीडबैक- समाधान के बाद यात्री से फीडबैक लिया जाता है ताकि सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके।

■उच्च तकनीक- वार रूम में उच्च तकनीक के उपकरण जैसे कि बड़े स्क्रीन, इंटरकॉम, कंप्यूटर आदि का उपयोग किया गया है।

■निरंतर निगरानी- 24×7 निगरानी और शिफ्टों में कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

रेलवे ने कहा

इस पहल से यात्री सेवाओं में वृद्धि हुई है और यात्रियों को बेहतर सेवा और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। भारतीय रेल द्वारा यह एक सराहनीय कदम है, जिससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के त्वरित और प्रभावी सहायता मिल रही है। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम भोपाल

बच्ची का अपहरण करने वाले निकले दो नाबालिग

दो साल पहले दोस्ती हुई फिर शौक पूरे करने के लिए बने किडनैपर

न्यूज क्राइम फाइल

दतिया के रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल से 3 जुलाई को हुए बच्ची के अपहरण के प्रयास के मामले में दो नाबालिग आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपने शौक पूरे करने के लिए बच्ची के अपहरण का प्लान बनाया था। पुलिस की पूछताछ में निकल कर सामने आया है आरोपी फिरौती में 30 लाख रूपए की डिमांड रखते। मामले का खुलासा करते हुए दतिया एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि 3 जुलाई को [redacted] स्कूल में पढ़ने वाली नर्सरी की छात्रा के अपहरण का प्रयास हुआ था। आरोपी ने बच्ची को अपनी बाइक पर बैठा लिया था। उसी समय बच्ची 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्ची के चाचा ने देख लिया। तो

आरोपी बच्ची को छोड़ कर भाग निकला। मामले की शिकायत थाने में की गई थी। पुलिस ने तुरंत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोतवाली थाना प्रभारी धीरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। जिस टीम ने घटना स्थल से लेकर आम रास्तों के करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इस के अलावा टीम के मुखबिर तंत्र भी एक्टिव हुए। जिस आधार पर पुलिस ने एक को ठंडी सड़क और दूसरे को झांसी बाय पास से राउंड अप किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। दोनों आरोपी नाबालिग है। पुलिस की पूछताछ में दोनों बताया कि उनकी दोस्ती करीब 2 साल पहले हुई थी। दोनों एक साथ जिम करते थे। 3 माह पहले अपने शौक पूरे करने के लिए किसी बच्चे का अपहरण करने का प्लान बनाया। फिरौती में अपहरण किए बच्चे के परिवार से 30 लाख रूपए की फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। इस के बाद दोनों बाल अपचारी शहर मे अलग अलग स्कूलों मे जाकर रैकी करने लगे। जिसके बाद उन्होंने आरएलपीएस स्कूल में पढने वाली 4 साल की बच्ची का अपहरण करने का प्लान बनाया और बच्ची के परिवार के बारे में जानकारी हासिल की। 2 जुलाई को दोनों बाल अपचारियों ने फिर से योजना बनाई कि हम बच्ची का अपहरण करके मो.सा. से झांसी ले जाएंगे। वहां से कार से उसे दक्षिण भारत ले जायेगे। फिर उसके बाद बच्ची के परिवार से हम 30 लाख रूपए की मांग करेगे। घटना के दिन एक आरोपी बच्ची के परिवारजनों के मकान के पास रेकी कर रहा था। दूसरा आरोपी आरएलपीएस स्कूल से बच्ची का अपहरण करने के लिए गया था।

मोहन सरकार के बजट में कितने 'संकल्प'

न्यूज क्राइम फाइल

'हमारे दल के संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने ग्रहण किया है। यह संकल्प पत्र हमारी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में निरंतर बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा।' मध्यप्रदेश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण की ये लाइनें 'पॉलिटिकली करेक्ट' हो सकती हैं लेकिन बजट में संकल्प पत्र की स्पष्ट तस्वीर नजर नहीं आ रही है।

महिला : छात्राओं की मुफ्त शिक्षा पर मौन

बजट का 33 फीसदी हिस्सा यानी 1.21 लाख करोड़ रुपए महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए है, महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की राशि का ऐलान तो किया ही है, साथ ही आवास के लिए 40 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया है। हालांकि, संकल्प पत्र में बीपीएल छात्राओं की केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा के ऐलान का बजट में जिक्र नहीं है।

किसान : गेंहू पर बोनस लेकिन धान पर नहीं

संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों को गेहूं और धान पर बोनस देने की बात की गई थी। सरकार ने बजट में गेहूं पर 125 रु. प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया है। इसके लिए 1 हजार करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन, धान पर बोनस का ऐलान नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण के हितग्राहियों को फायदा देने की बात बजट में की गई है, जिसका जिक्र संकल्प पत्र में भी किया गया है। वहीं संकल्प पत्र में किसानों को 3 हजार प्रतिमाह पेंशन देने की बात की गई थी, लेकिन बजट भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया।

आदिवासी और अनुसूचित जाति : 5 साल में 3 लाख करोड़ का संकल्प, बजट में 40 हजार करोड़

जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए संकल्प पत्र में 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए उनकी बेहतरी पर खर्च करने का उल्लेख है, लेकिन चुनाव बाद के पहले बजट में सरकार इस पर जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। हालांकि, अनुसूचित जाति का कुल बजट 40 हजार 804 करोड़ रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास के स्मारक निर्माण का संकल्प पत्र में जिक्र था। इसका काम चल रहा है। इसके अलावा सरकार ने 30 जिलों में स्मारक बनाने की घोषणा की है।

युवा और शिक्षा : 60 हजार नौकरियों का ऐलान

यूनिफॉर्म और किताबें फ्री देने की घोषणा पर सरकार ने तुरंत अमल किया है। नौकरियां देने पर भी सरकार ने बजट में ही ऐलान कर दिया है। इससे युवाओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि, आईआईटी की तर्ज पर एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाने पर सरकार ने अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर : 6 एक्सप्रेस-वे का ऐलान, इलेक्ट्रिक बसें चलाने के वादे पर भी काम शुरू

सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा दिखा है। संकल्प पत्र में जो 6 एक्सप्रेस- वे बनाने

का वादा था, उस पर बजट में ऐलान हुआ है। हालांकि, ये दीर्घकालिक योजना है। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के वादे पर भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मेट्रो को जल्द पूरा करने का संकल्प बजट में भी दोहराया है।

जिन योजनाओं को लेकर बजट जारी हुआ, उनमें सीएम की दिलचस्पी

वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मेनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। बीजेपी ने सारे वादे शिवराज से करवाए थे। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव न तो मेनिफेस्टो कमेटी में थे न इसे बनाने में उनका कोई रोल था। जब वे सीएम बने तो साफ दिखाई दे रहा है कि उनका विजन अलग है और शिवराज का विजन अलग था। जाहिर तौर पर वो कुछ बातों पर सुस्त होंगे कुछ पर तेज चलेंगे। अब मेनिफेस्टो पार्टी का होता है तो पार्टी को 5 साल बाद जवाब देना पड़ेगा। अभी जिन योजनाओं को लेकर टोकन बजट जारी हुआ है। उनमें भी मोहन यादव की दिलचस्पी दिखती है, बाकी में नहीं दिखती। एन के सिंह कहते हैं कि सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है ये बजट देखकर समझ आता है। जो 16 प्रतिशत बजट बढ़ा है वो पैसा तो ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। पिछली सरकार को जीतने की उम्मीद नहीं थी तो उसने ढेर सारे वादे किए और बाजार से कर्ज उठाया।

भोपाल में सोशल मीडिया फ्रेंड ने महिला से की ज्यादती

न्यूज क्राइम फाइल

पति से तलाक के बाद महिला सोशल मीडिया के जरिए भोपाल के युवक के संपर्क में आ गई। दोनों के बीच दोस्ती हुई तथा शादी की बात चलने लगी तो युवक ने महिला को परिवार से मिलाने के बहाने बुलाया। यहां पर फ्लैट में उसने महिला को डरा-धमकाकर उसके साथ रेप किया। बाद में शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करना लगा। पिछले दिनों जब उसने शादी करने से मना कर दिया तो महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय महिला मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है। उसका अपने पति से तलाक हो चुका है। अब वह अपनी बच्ची के साथ रहती है। करीब चार साल पहले उसकी सोशल मीडिया के जरिए

पहचान भोपाल के बैरागढ़ इलाके में रहने वाले दिनेश बगलानी नाम के युवक से हो गई थी। दोनों के बीच कई महीनों तक बातचीत व चैटिंग चलती रही। बातचीत के दौरान महिला ने अपनी जिंदगी की सभी निजी बातें युवक के साथ शेयर की। महिला की बातें सुनने के बाद युवक ने महिला से कहा कि वह शादी करना चाहता है। महिला ने हामी भरते हुए भोपाल में काम की तलाश शुरू कर दी। उसने करोंद इलाके के कए अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अक्टूबर 2022 में युवक ने महिला से कहा कि वह शादी की बात करने के लिए महिला को अपने परिवार से मिलाना चाहता है। युवक की बात को मानते हुए महिला भोपाल आ गई। फ्लैट पर युवक तो पहुंच गया लेकिन परिवार उसके साथ नहीं था। महिला को अकेला पाकर युवक ने उसको जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ रेप किया। महिला ने जब पुलिस थाने में शिकायत करने की बात कही तो युवक ने महिला को शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद वह शारीरिक शोषण करता रहा। गत 22 जून को भी उसने महिला के साथ ज्यादती की। महिला ने शादी की बात का दबाव डाला तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी।

सागर के हर घर में उल्टी-दस्त के पेशेंट...

किसी घर के सभी सदस्य बीमार; सागर में गांव के लोगों में दहशत

न्यूज क्राइम फाइल

सागर जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर स्थित ग्राम मेहर डायरिया फैल गया। यहां हर घर में उल्टी-दस्त के मरीज हैं। किसी घर के सभी सदस्य बीमार हैं। गांव के 250 से अधिक लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित हैं। इनमें से एक की मौत हो गई। अस्पतालों में भर्ती मरीजों में बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। करीब 70 मरीजों का इलाज सागर जिला अस्पताल, बीएमसी और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत है। सभी लोग घबराए हुए हैं। गांव में मरीजों के इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र मेहर, आयुर्वेदिक अस्पताल और छात्रावास को अस्थाई अस्पताल बनाया गया है। यहां 30 से अधिक पलंग लगाकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ग्रामीणों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने के पीछे कारण पानी बताया जा रहा है। गांव के ट्यूबवेल का पानी पीने से लोग उल्टी-दस्त के शिकार हुए हैं। हालांकि कुछ ग्रामीण पानी से उल्टी-दस्त होने की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पिछले करीब 30 साल से ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं। इससे पहले कभी पानी के कारण कोई बीमार नहीं पड़ा। इस बार भी यदि पानी से लोग बीमार हुए होते तो गांव के अन्य लोग भी उल्टी-दस्त के शिकार होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गांव से सिर्फ तीन मोहल्ले आदिवासी मोहल्ला, रविदास वार्ड नारायणपुरा, ऊपर टोला में ही लोग सबसे ज्यादा बीमार हुए हैं। स्थिति ये है कि हर घर में उल्टी-दस्त का मरीज है। वहीं, कुछ घरों में तो परिवार के सभी सदस्य बीमारी की चपेट में आए हैं। हालांकि मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि प्राथमिक रूप से पानी के कारण लोगों के बीमार होने की संभावना है। ट्यूबवेल को सात दिनों के लिए बंद कराकर पानी के सैंपल लिए गए हैं। सेंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कारण सामने आ सकेगा।

ट्यूबवेल से 80 फीसदी गांव के लोग पीते हैं पानी

मेहर गांव की करीब 5000 की आबादी है। सरकारी ट्यूबवेल से गांव के 80 फीसदी घरों में पानी की सप्लायी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी ट्यूबवेल करीब 30 साल पुराना है। गर्मी के मौसम में एकमात्र इसी ट्यूबवेल से गांव के घरों में पानी सप्लायी होता है। कुछ लोग अपने निजी बोर और कुओं के पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन गांव के तीन मोहल्लों में ही सबसे ज्यादा लोग उल्टी-दस्त के शिकार हुए हैं। इस कारण पानी से लोगों के बीमार होने पर ग्रामीण संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश भी इतनी नहीं हुई कि ट्यूबवेल का पानी दूषित हो जाए।

4 बच्चों के पिता की मौत, परिवार के 8 लोग भर्ती

उल्टी-दस्त से ग्रसित हुए मरीज लल्लन बंसल उम्र 40 साल निवासी मेहर की इलाज के दौरान गुरुवार रात बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। लल्लन मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। मृतक के चचेरे भाई मूलचंद बंसल ने बताया कि परिवार के 8 लोग उल्टी-दस्त होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं चचेरे भाई लल्लन बंसल की इलाज के दौरान मौत हो गई। लल्लन की अचानक तबीयत बिगड़ी और हाथ-पैर अकड़ने लगे। अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिला। अब परिवार को अस्पताल में भर्ती बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है।

नदी से नहाकर आई और हो गई बीमार

मरीज के बेटे विक्रम ने बताया कि मां दोपहर 12 बजे धसान नदी में नहाने के लिए गई थी। वहां से लौटकर घर आई तो तबीयत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त होने लगे। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक से उल्टी-दस्त होने पर तत्काल अस्पताल भर्ती कराया है। जहां इलाज चल रहा है। तबीयत क्यों बिगड़ी, कुछ कह नहीं सकते। मरीज उत्तम सेन ने बताया कि गुरुवार शाम को एक रोटी खाई थी। जिसके बाद 12 बजे से उल्टी-दस्त होने लगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लगातार उल्टी-दस्त हो रहे हैं। मेरी मां श्यामरानी सेन भी उल्टी-दस्त से ग्रसित हैं।

30 सालों से पानी पी रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ

ग्रामीण दशरथ अहिरवार ने बताया कि गांव में गर्मी के मौसम में सिर्फ सरकारी ट्यूबवेल में ही पानी रह जाता है। इसी से गांव में पीने के पानी की सप्लायी होती है। पिछले करीब 30 सालों से ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक कोई भी पानी पीने के कारण बीमार नहीं पड़ा है। लेकिन अब पूरा मोहल्ला ही बीमार हो गया। समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। अधिकारियों ने ट्यूबवेल को बंद करा दिया है।

8 साल पहले भी गांव के लोग हुए थे उल्टी-दस्त के शिकार

नरयावली क्षेत्र में करीब 35 सालों से स्वास्थ्य सेवा में काम कर रही एएनएम ममता चौरसिया ने बताया कि संभवत: दूषित पानी पीने के कारण लोगों को उल्टी-दस्त हो रहे हैं। करीब 7 से 8 साल पहले भी गांव के नारायणपुरा मोहल्ले में यही हालात बने थे। उस समय भी मैं ड्यूटी करने आई थी। बड़ी संख्या में गांव के लोग उल्टी-दस्त के शिकार हुए थे। ठीक वैसी ही स्थित अब बनी है।

पानी के कारण ही बीमार हुए लोग

छात्रावास में बनाए गए अस्थाई अस्पताल में तैनात आयुष मेडिकल ऑफिसर तपस्या रानी ने बताया कि यहां दो दिन से कालरा फैला है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और मरीजों का इलाज कर रही है। गांव में तीन केंद्रों पर लगातार मरीजों का उपचार किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रैफर कर रहे हैं। जिस बोर का पानी पीने से लोग बीमार पड़े हैं, उसे बंद करा दिया गया है। प्राथमिक रूप से तो पानी पीने के कारण ही लोगों की तबीयत खराब होना लग रहा है। गांव में दूसरा कोई कारण समझ नहीं आ रहा है।

पुलिसकर्मियों ने छिपकर बचाई जान

पुलिस चौकी में तोड़फोड़, बंदियों को छुड़ा ले गई भीड़...

मारपीट की एफआईआर करा रहे लोगों को पीटा

न्यूज क्राइम फाइल

गुना में 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी में धावा बोला दिया और दो बंदियों को छुड़ाकर ले गई। रिपोर्ट लिखा रहे चार लोगों को लाठी-डंडों से पीटा। चौकी में तोड़फोड़ की। वहां खड़ी सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार रात में हुई इस घटना के बाद शनिवार दोपहर को खुद एसपी संजीव कुमार सिंह चौकी पहुंचे। मामला जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके का है। यहां हरिपुरा गांव में दो पक्ष के लोग भिड़ गए थे। विवाद गुमटी रखने को लेकर हुआ। पुलिस दो युवकों को पकड़कर उकावद चौकी ले आई। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग इकट्ठा होकर चौकी पहुंच गए। घटना के समय चौकी में सिर्फ दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। इस समय दूसरे पक्ष से शिकायत करने आए चार लोग भी थे, जो बचाव के लिए बाथरूम में घुस गए। हमलावर गेट तोड़कर उन्हें बाहर घसीट लाए और लाठी-डंडों से पीटा।

चौकी में ही हमें 15 मिनट तक पीटा

हमले में घायल सरजन सिंह गुर्जर, जसमन गुर्जर, राधेश्याम गुर्जर, सीताराम गुर्जर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरजन गुर्जर ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें 15 मिनट तक बुरी तरह पीटा। सरजन ने बताया कि एक दिन पहले मामा के लड़के रतन गुर्जर से आरोपी बबलू गुर्जर और हिम्मत लोधी का झगड़ा हुआ था। इसी बात पर शुक्रवार रात आरोपी हमारे घर आ धमके और मारपीट की।

बदमाशों को बुलाकर हमला कराया

सरजन के मुताबिक, बबलू गुर्जर और हिम्मत सिंह लोधी ने चौकी में बदमाशों को बुला लिया था। सभी पुलिस की ओर भी लाठी लेकर दौड़े। वे छिप गए। जसमन गुर्जर का कहना है कि हम रिपोर्ट लिखाने चौकी गए थे। इतने में 40 - 50 लोग आ गए। हमारे साथ मारपीट की। चौकी के गेट तोड़ दिए।

निगमकर्मी मृत, फिर भी सैलरी निकली,अब जांच

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल नगर निगम के एक सफाई सुपरवाइजर की मृत्यु होने के बावजूद सैलरी निकलने और कंट्रक्शन से जुड़े मुद्दे की जांच शुरू हो गई है। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कांग्रेस पार्षद शिरीन खान ने निगम बैठक में यह मुद्दा उठाया था। इसके अलावा एमआईसी मेंबर के जवाब और आरटीआई (राइट टू इंफॉरमेंशन) में निर्माण कार्यों की अलग-अलग रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। वार्ड-35 की पार्षद शिरीन ने बताया, जोन-7 में मेरा वार्ड-35 है। कौन सा कर्मचारी कहां पदस्थ हैं और क्या काम कर रहा है, इसकी जानकारी ली गई थी। आरटीआई में जानकारी ली कि मेरे वार्ड के सुपरवाइजर जसवंत की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी सैलरी निकल रही है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। इसकी जांच की मांग की गई थी। इस मामले में निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने बताया, सैलरी के मामले में कमिश्नर को बारीकीं से जांच करने को कहा है। इसमें जो कर्मचारी भी दोषी पाया जाता है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। निगम कमिश्नर को जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। एक-दो दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।

निर्माण कार्य में गड़बड़ी की आशंका

कांग्रेस के वार्ड-77 के कांग्रेस पार्षद दानिश खान नेब ताया, अपने वार्ड के एक निर्माण को लेकर सवाल उठाए। मुझे एमआईसी मेंबर से लिखित जवाब मिला कि यह कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। दूसरी ओर, आरटीआई में कार्य होने की जानकारी दी गई है। इस मामले में भी बारीकीं से जांच हो।

हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

न्यूज क्राइम फाइल

देवास जिले में 3 जून को जवाहर नगर क्षेत्र में गोली मारकर हुई कुणाल उर्फ चीकू बैरागी की हत्या के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंब्रेश प्रसाद सहित एक अन्य आरोपी भावेश दोनों निवासी देवास को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अंब्रेश प्रसाद राजस्थान भागने की फिराक में था। मामले में आरोपी के अन्य दो साथियों की भूमिका की जांच की जा रही है। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि आमरेश और शैलेंद्र पवार दोनों पहले दोस्त थे और साथ में दोनों आरोपी भी रहे हैं। दोनों में वर्चस्व को लेकर और लेनदेन को लेकर मतभेद हो गए और दोनों आपस में रंजिश रखने लगे उसी के चलते दोनों गुट के लोग आपस में रंजिश रखते थे। उसी के चलते यह गोली चलाई गई थी। जिसमें कुणाल बैरागी की मौत हुई थी। विवाद के पहले सभी जेल गए थे वहां पर धमकी देने पर भी पुलिस ने कुछ लोगों को आरोपी बनाया है। साथ आरोपी अंब्रेश के घर तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपी शैलेंद्र पवार सहित उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर इनके पास से दो पिस्टल व 8 जिंदा राउंड जब्त किए गए।

बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक

बजट 23 जुलाई को, सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी

संदीप कुमार सिंह

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था।

अब बजट की पूरी प्रोसेस को समझिए

1. सबसे पहले वित्त मंत्रालय एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए कहता है। उन्हें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल के खर्च और आमदनी का ब्योरा भी देना होता है।

2. एस्टिमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। इस पर संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है। इसके बाद आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है।

3. वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करता है। राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को गहराई से समझने के लिए किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है।

4. प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। इनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्री-बजट मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सभी मांगों पर अंतिम फैसला लेते हैं। बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं।

5.बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है। एक बड़ी सी कढ़ाई में तैयार किया जाने वाला हलवा वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई।

6.वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं। 2016 तक यह फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। 2017 से यह हर साल 1 फरवरी को पेश होने लगा। इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेज मोबाइल पर उपलब्ध कराए गए।

फुल और अंतरिम बजट होता क्या है इनमें क्या अंतर है

केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा-जोखा होता है। यूं कहें कि बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वहीं अंतरिम बजट सरकार को आम चुनावों का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक, देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है।

हाथरस भगदड़- मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल

कोर्ट से दौड़ाकर बाहर लाई पुलिस, मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर

न्यूज क्राइम फाइल

हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में मीडिया का जमावड़ा था। पुलिस मीडिया से बचने के लिए मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़ाकर बाहर लाई, तभी वह मुंह के बल गिर पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उसे तेजी से संभाला और फिर दौड़ाते हुए जीप में बिठाकर ले गए। मधुकर और उसके एक अन्य साथी संजीव यादव को अलीगढ़ जेल भेजा गया है। सुबह 11 बजे पुलिस ने मधुकर का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। बाहर निकला तो उसका मुंह अंगौछे से बंधा था। मीडिया कर्मियों ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन देव प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। देव प्रकाश को शुक्रवार रात दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। निपुण अग्रवाल ने कहा- मधुकर फंड जुटाता था। कुछ समय पहले उससे राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था। अब जांच होगी कि पार्टियों ने फंडिंग तो नहीं की थी। उधर, बिहार के पटना में हादसे को लेकर बीजेपी नेता ने भोले बाबा पर केस दर्ज कराया है। हादसे के बाद शनिवार सुबह पहली बार भोले बाबा सामने आया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा- हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना से बहुत दुखी हैं। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन के लिए अलीगढ़ जेल भेज दिया है। कोर्ट में मीडिया का जमावड़ा था। मीडिया के सवालों से बचने के लिए पुलिस देव प्रकाश को पीछे के दरवाजे से दौड़ाते हुए बाहर लाई। उसका चेहरा रूमाल से बंधा था। तभी मधुकर का पैर फिसला और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उसे तेजी से संभाला और फिर दौड़ाते हुए जीप में बिठाकर ले गए। पुलिस ने मधुकर के साथी संजीव यादव को भी कोर्ट में पेश किया था। उसे भी 14 दिन के लिए अलीगढ़ जेल भेज दिया गया है।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक उदय प्रताप सिंह चौहान द्वारा कविता ऑफसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- उदय प्रताप सिंह चौहान, मो.7223003441 (प्रति सोमवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2015/63623